

## बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 12 अंक 288

### स्वामीयुक्त नीति

चालू वित्त वर्ष के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य में भारी कमी की आशंका के चलते सरकार वैकल्पिक रास्ते देख रही है। खबरों के मुताबिक अब वह सरकारी उपक्रमों के स्वामित्व वाली संपत्ति बेचकर मार्च के अंत तक एक लाख करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। जिन परिसंपत्तियों पर बिक्री के लिए विचार किया जा रहा है

उनमें भूमि और पाइपलाइन, सड़क, मोबाइल टावर, बिजली, सरकारी उपक्रमों के स्वामित्व वाली परेषण लाइन आदि शामिल हैं। परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण का विचार जहां आगे बढ़ाने योग्य है, वहीं सशस्त्र बलों और रेलवे आदि सरकार की विभिन्न शाखाओं के पास शहरी इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी जमीन है जिनके लिए

डेवलपर बहुत बड़ी राशि चुकाने को तैयार होंगे। परंतु दी गई अवधि में यह बिक्री करना लगभग असंभव है। इसके अलावा इसके लिए जिस तरह प्रयास किए जा रहे हैं वह बुनियादी रूप से गलत है। पहली बात तो यह लक्षित परिसंपत्तियां मोटे तौर पर सरकारी उपक्रमों की हैं। इन्हें मजबूरी में बेचकर हासिल होने वाली राशि सरकार को लाभांश के रूप में देनी होगी। यह सरकारी उपक्रमों की काम करने की स्वायत्तता के खिलाफ है। दूसरी बात, परिसंपत्तियों की बिक्री पर विचार करने के लिए वित्त वर्ष के लगभग अंत का समय है। जाहिर है ऐसा केवल बजट लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया गया है। इसका असर मूल्यांकन और हासिल होने

वाली राशि पर पड़ सकता है। इतना ही नहीं इससे वैधानिक जटिलताएं भी पैदा हो सकती हैं। स्पष्ट है कि सरकार यह विकल्प इसलिए चुनना चाहती है क्योंकि चालू वर्ष में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया पूरी होती नहीं दिखती। इसके लिए भी खराब योजना ही जिम्मेदार है। चूंकि राजस्व संग्रह में अहम कमी आने वाली है तो ऐसे में विनिवेश के मोर्चे पर कमजोर प्रदर्शन राजकोषीय प्रबंधन को और जटिल बना देगा। चालू वर्ष में सरकार अब तक 18,095 करोड़ रुपये ही जुटा सकी है जो विनिवेश लक्ष्य का 17 फीसदी है। सरकार विनिवेश लक्ष्य हासिल करने में इसलिए भी संघर्ष करती है क्योंकि वह इस विषय पर

व्यवस्थित तरीके से काम नहीं करती। उदाहरण के लिए यदि सरकार व्यापक रणनीतिक विनिवेश करना चाहती है तो उसे वित्त वर्ष के आरंभ में ही नामों का चयन कर लेना चाहिए। इसे अमल में लाने में समय लगता है क्योंकि संभावित खरीदार उचित जांच-परख करना चाहते हैं। सरकारी उपक्रमों की परिसंपत्ति बेचने का विचार नीति निर्माण में खामी का एक अमल उदाहरण है। ऐसे में सही यही होगा कि सरकार ऐसे सरकारी उपक्रमों की सूची तैयार रखे जिनमें वह मध्यम अवधि में विनिवेश करना चाहती है। यह विनिवेश अंशकालिक भी हो सकता है और सामरिक भी। इस प्रक्रिया को अन्य परिसंपत्तियों मसलन भूमि आदि में भी अपनाया चाहिए। इससे न केवल सरकार

को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी बल्कि इससे बाजार भागीदारों को तैयारी और बोली लगाने के लिए उचित समय भी मिलेगा। ऐसी प्रक्रिया अपनाने से बोली लगाने वालों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और मूल्यांकन सुधरेगा। इससे सरकार को भी इस बात का बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि मध्यम अवधि में पैसा कैसे जुटाया जा सकता है। आदर्श स्थिति में परिसंपत्ति बिक्री को पूरी तरह घाटे में पूर्ति करने के विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस प्रक्रिया से हासिल राजस्व का इस्तेमाल नई परिसंपत्तियां तैयार करने में किया जाना चाहिए। इससे मध्यम से दीर्घ अवधि में संभावित वृद्धि को तेज करने में मदद मिलेगी।



विजय शिन्हा

# थोड़ी स्थिरता हासिल मगर जोखिम बाकी

धीरे-धीरे वृद्धि में स्थिरता आ रही है लेकिन अभी भी कई चक्रीय कारक मौजूद हैं जिनका जोखिम बरकरार है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं नीलकंठ मिश्रा

मांग में कमी से उत्पन्न आर्थिक मंदी की इकलौती अच्छी बात यह है कि माल कम करने से वह समाप्त हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कटौती अनंतकाल तक जारी नहीं रखी जा सकती है। बीती छह तिमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में जो गिरावट आई है उसकी एक अहम बात है इन्वेंटरी में गिरावट। जीडीपी में जब गतिविधियों का आकलन किया जाता है तो इन्वेंटरी का आकार वृद्धि में जोड़ा जाता है। कम इन्वेंटरी का असर उलटा होता है। बीती छह तिमाहियों में सेवा और उद्योग जगत में वृद्धि के अंतर तथा जीएसटी संग्रह में कमी में इसे महसूस किया जा सकता है। तिमाही सेवा वृद्धि के आकलन में दिक्कत हो सकती है लेकिन इसमें उद्योग की तरह गिरावट नहीं आती है। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेवा क्षेत्र में ज्यादा इन्वेंटरी नहीं हो सकती। इससे पहले ऐसा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत के पहले वाली तिमाही में देखने को मिला था। उस वक्त उद्योग और सेवा की वृद्धि में समान भिन्नता नजर आई थी। वस्तु आपूर्ति शृंखला ने इन्वेंटरी कम करके जीएसटी के साथ नई शुरुआत करने की सोची। बीती पांच

तिमाहियों में ऐसा वित्तीय हालात तंग होने से हुआ। क्योंकि इसका असर वित्तकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा कारोबारियों को ऋण की उपलब्धता पर पड़ा। ऐसे प्रमाण हैं कि माल में कमी का दौर अब समाप्त हो चुका है। बिजली की मांग वृद्धि जो अक्टूबर और नवंबर में दो अंक में थी वह दिसंबर में केवल 2 फीसदी कम रही। जनवरी के पहले सप्ताह में इसमें मामूली इजाफा हुआ। जीएसटी संग्रह और रेल मालवहन भी सकारात्मक वृद्धि दर्शा रहे हैं। ये आंकड़े अभी भी कमजोर हैं लेकिन पहले आई तीव्र कमी से तो बेहतर ही हैं। यदि बाकी सब सामान्य रहा तो एक बार फिर इन्वेंटरी भरनी शुरू हो जाएगी और इसका लाभ वृद्धि को मिलेगा।

परंतु वित्तीय स्थिति तंग बनी हुई है। जिन वित्तीय कंपनियों के पास पूंजी, उत्पाद और पूंजी तक पहुंच है वे भी वृद्धि में धीमेपन के चलते ऋण देना कम कर रही हैं। नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर आधी हो जाने के बाद यदि मौजूदा कर्जदारों के लिए ऋण की गुणवत्ता का नए सिरे से आकलन किया जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वय्य में कटौती वृद्धि की राह में एक और बाधा

होगी क्योंकि वे ऐसे वर्ष में अपने राजकोषीय घाटे को पूर्ति करने का प्रयास करेंगे जहां कर प्राप्ति तय लक्ष्य से कम रही हो। पहले आठ महीनों के दौरान केंद्र सरकार का वय्य 13 फीसदी बढ़ा। लेकिन प्राप्ति में कमी को देखते हुए यदि यह राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कायम रहा तो अंतिम चार महीनों में वय्य पिछले साल से एक फीसदी कम होगा। यदि विनिवेश प्रक्रिया बजट से कमजोर रही तो कहीं अधिक कटौती कमी उत्पन्न हो जाएगी। राज्य सरकारों के लिए वित्त वर्ष के मध्य तक ऋण के लक्ष्य स्थिर हो जाते हैं और वे अपने घाटे में और इजाफा नहीं कर सकते। उनके लिए वय्य में कटौती करना आवश्यक है। वे पहले ही भुगतान करने में देरी कर रही हैं। उदाहरण के लिए फसल बीमा का नुकसान। बल्कि वित्त वर्ष के अंत तक राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में भी देरी हो सकती है। ऐसे कदमों से कमजोर उपभोक्ता रुझान और कमजोर हो सकते हैं और कंपनियों की निवेश योजनाएं और कमजोर हो सकती हैं। कई नैसर्गिक स्थिरता प्रदान करने वाले कारक अब काम नहीं कर रहे हैं। कमजोर आर्थिक वृद्धि प्रायः ब्याज दरों को प्रभावित करती है लेकिन जैसा कि हम अक्सर कहते

आए हैं कमजोर वृद्धि और कम मुद्रास्फीति के बावजूद कर्जदारों के लिए ब्याज दर अपरिवर्तित रही है।

गत वर्ष देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी जीडीपी के दो फीसदी से अधिक का इजाफा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूंजीगत आवक और निर्यात तब भी बढ़े जब कमजोर घरेलू मांग से आयात कम हुआ। यदि विदेशी बचतकर्ता देश की जरूरत से अधिक धन देना चाहते हैं तो या तो मुद्रा का अधिमूल्यन होगा या फंड की लागत घटेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी बॉन्ड खरीदने का एक जोखिम यह है कि मुद्रा कमजोर होगी लेकिन भुगतान संतुलन का ऐसा अधिशेष दिखाता है कि फिलहाल ऐसा कोई जोखिम नहीं है।

आम चर्चा की बात करें तो बीते कुछ महीनों में बैलेंस शीट की समस्याओं की तादाद बढ़ी है। वह सही हो सकती है और हमें यह याद रखना चाहिए कि बैलेंस शीट पर दबाव कमजोर वृद्धि के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा चोरी या भ्रष्टाचार के कारण हो। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार का 45 प्रतिशत का ऋण-जीडीपी अनुपात स्थायी नजर आया और उसमें निरंतर गिरावट आ रही है क्योंकि नॉमिनल वृद्धि दर ऊंची रही लेकिन वृद्धि में धीमापन आने और ऋण की लागत के करीब 7 फीसदी तथा ब्याज दर के जीडीपी के 3 फीसदी रहने के कारण जीडीपी अचानक खस्ता नजर आने लगी। गत वर्ष ये वृद्धिकारी वय्य का तिहाई था। यदि कर 8 फीसदी की दर से बढ़ते हैं और नॉमिनल जीडीपी के अनुरूप गैर विवेकाधीन वय्य मसलन ब्याज और वेतन आदि उसी गति से बढ़ते हैं तो राजकोषीय समावेशन कैसे होगा? अतिरिक्त वय्य की तो बात ही छोड़ दी जाए। यदि नॉमिनल जीडीपी वृद्धि में आया धीमापन तनावग्रस्त ऋण को बढ़ावा देता है तो सही उपाय यही होगा कि वृद्धि को गति प्रदान की जाए, न कि बैलेंस शीट सुधारने की कवायद की जाए।

आर्थिक कारक समय-समय पर अपनी भूमिका निभाते हैं भले ही यह वांछित से धीमी गति से हो। कम ब्याज दर पर बात करें तो वृद्धि में सुधार के लिए वह आवश्यक है। बैंक जमा दर में गिरावट आने लगी है और समय बीतने के साथ इसका असर ऋण दर पर भी पड़ेगा। मॉर्गेंज दर बीते पांच महीने में करीब 50 आधार अंक कम हुई है। बजट प्रस्तुत होने के बाद राजकोषीय घाटे और वय्य को लेकर अनिश्चितता कुछ हद तक कम होगी। अप्रैल के बाद केंद्र और राज्य सरकारें वय्य सुधारने में कामयाब हो सकती हैं। तब तक संभवतः शीघ्र मुद्रास्फीति भी सार्थक सुधार के साथ नजर आए। यदि वित्तीय तंत्र में कोई और गड़बड़ी नहीं होती है तो तब तक राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में भी देरी हो सकती है। ऐसे कदमों से कमजोर उपभोक्ता रुझान और कमजोर हो सकते हैं और कंपनियों की निवेश योजनाएं और कमजोर हो सकती हैं। कई नैसर्गिक स्थिरता प्रदान करने वाले कारक अब काम नहीं कर रहे हैं। कमजोर आर्थिक वृद्धि प्रायः ब्याज दरों को प्रभावित करती है लेकिन जैसा कि हम अक्सर कहते

## सेना के तीनों अंगों की एकीकृत थिएटर कमान पर विचार जरूरी

सेना के उच्च प्रबंधन को मजबूत करने की चर्चाओं में आम तौर पर दो सुधारों की जरूरत पर सहमति होती है। पहली जरूरत सेना के तीनों अंगों- थलसेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल बिठाने के लिए एकीकृत प्रमुख की नियुक्ति है। भारत के पहले सैन्य-अलग प्रमुख (सीडीएस) की नियुक्ति के साथ आंशिक तौर पर इसे पूरा किया जा चुका है। सीडीएस को तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बनाने का जिम्मा दिया गया है लेकिन वह ट्राई-सर्विस मसले पर ही सरकार को परामर्श देगा और तीनों सेनाओं के प्रमुख अपने बल के अंगों में पहले की तरह सलाह देते रहेंगे। अधिकतर विशेषज्ञ इस जरूरत पर सहमत हैं कि तीनों सेनाओं को साथ आकर ट्राई-सर्विस लड़ाकू कमान बनानी चाहिए। एक भौगोलिक क्षेत्र में तीनों सेनाओं की कमान अलग होती है, मसलन सेना की उत्तरी कमान, वायुसेना की पश्चिमी कमान और नौसेना की दक्षिणी कमान। तर्क यह रहा है कि तीनों सेनाओं की एकीकृत कमान बनाकर यह अलगाव खत्म किया जाए। इस कमान को जंग की स्थिति में लड़ाकू अभियान चलाने के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जरूरी सभी अधिकार होंगे। अंडमान एवं निकोबार कमान में ऐसी एकीकृत कमान पहले से मौजूद है लेकिन उस प्रायोगिक अनुभव को आगे नहीं बढ़ाया गया। एकीकृत कमान की अवधारणा सबसे पहले अमेरिका ने लागू की थी। उसने 1947 में पांच क्षेत्रों के लिए पांच युद्धक कमान गठित की थी। मध्य कमान, अफ्रीका कमान और हिंद-प्रशांत कमान जैसे नाम पूरी दुनिया को ही कवर करते थे। चीन की सेना ने भी 2016 में यह मॉडल अपनाते हुए पांच संयुक्त थिएटर कमान में पुनर्गठन किया।

साझा नेतृत्व जहां सैन्यबलों के पुनर्गठन और उपकरणों की खरीद में किफायत बरतने में मदद करता है, वहीं साझा थिएटर कमान ढांचा लागू करने के पहले काफी सोच-विचार करना होगा। भारतीय वायुसेना ने थिएटर कमान व्यवस्था का लगातार विरोध किया है। हमें उसकी दलीलों पर ध्यान देना चाहिए। पहली, लड़ाकू विमानों के तीव्र रफ्तार से उड़ान भरने और तेजी से भौगोलिक दायरा बदलने



दोधारी तलवार

अजय शुक्ला

को आधार बनाते हुए वायुसेना कहती है कि पूरा भारत एक ही भौगोलिक थिएटर है। वहीं अपेक्षाकृत धीमी रफ्तार वाली थलसेना और नौसैनिक पोतों को भौगोलिक आधार पर एक समूह में रखना तर्कसंगत लगता है। लेकिन यह भी सही है कि लड़ाकू विमान जिस तरह मिनों में ही दूसरी जगह जा सकते हैं, उसी तरह वे एक से दूसरी लड़ाकू भूमिका भी अपना सकते हैं। पाकिस्तान के अंतर्गत शिबिर पर गत फरवरी में हुए हमले के दौरान मिराज-2000 विमानों ने मध्य कमान में स्थित ग्वालियर से उड़ान भरी थी और पश्चिमी थिएटर से भी दूर के निशाने पर धावा बोला था। उस अंतर-थिएटर अभियान में मिराज विमानों ने 1,500 किलोमीटर से अधिक उड़ान भरी और हवा में ही ईंधन भरा गया।

ऐसे ही किसी अभियान में लड़ाकू विमान ग्वालियर से उड़ते हुए पूर्वी थिएटर में जाकर मैकमोहन रखा के पार भी हमला कर सकते हैं। इसमें उड़ान भरने से लेकर निशाना लगाने तक केवल एक घंटे का वक्त लगेगा और हवा में ईंधन भरने की भी सीमित जरूरत पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि मिराज-2000 विमान वापस लौटते समय आसानी से तेजपुर या चाबुआ के एयरफोर्स स्टेशन पर उतरकर ईंधन भर सकते हैं। एक लड़ाकू विमान के लिए दूसरे कमान क्षेत्र में जाकर कार्यवाही करना बेहद आसान है। दूसरी, ऐसे अभियानों में अलग-अलग थिएटरों के बीच समन्वय बनाना कठिन है। पाकिस्तान और चीन के हवाई क्षेत्र में जाकर हमला करने के लिए आज एक पूरा पैक चाहिए। हमलावर विमान को वायु प्रतिरक्षा एस्कॉर्ट, इलेक्ट्रॉनिक जंगी विमान, हवा में ईंधन भरने वाले विमान और हवाई चैतावनी एवं निनंत्रण

प्रणाली की भी जरूरत होगी। यह पैकेज कई एयरबेस से जुटाए विमानों से ही तैयार होगा क्योंकि एक बेस में सभी मौजूद नहीं होती हैं। ऐसे में सभी तरह के विमानों के उड़ाने भरने में बेहद सटीक समन्वय जरूरी होगा ताकि तय समय पर वे उपलब्ध रहें। लेकिन अलग-अलग थिएटर कमान में बांटे जाने पर ऐसा होना मुश्किल होगा। हेरक थिएटर कमांडर अपने काम को सबसे आगे रखेगा और दूसरे थिएटरों में हमले के लिए संसाधन देने में हिचकेंगे। तीसरी, वायुसेना की युद्धक क्षमता महज 28 स्कवाड्रन है। इन्हें अगर तीन या चार थिएटरों में बांटे दिया जाए तो स्थिति कमजोर हो जाएगी। विशाल वायुसेनाएं ही अपने विमान अलग थिएटर कमान में देने का जोखिम उठा सकती हैं। भारत का हवाई क्षेत्र चीन के पश्चिमी थिएटर कमान से भी छोटा है, लिहाजा भारतीय वायुसेना एक थिएटर का ही हिस्सा रह सकती है। चौथी, एकल थिएटर आधार पर परिचालन के लिए वायुसेना को निनंत्रण एवं निनियोजन केंद्रीकृत करना होगा जबकि क्रियान्वयन को विकेंद्रित रखना होगा। जंगी स्वाइडनों के अपने स्थायी ठिकाने हैं लेकिन किसी भी थिएटर में अभियान अंजाम देने के लिए एक पायलट को दूसरी जगहों पर भेजकर अनुभव दिलाना होगा। इस तरह का लचीलापन लाना मुश्किल होगा।

पांचवीं, भारत के हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए वायुसेना को केंद्रीकृत निनंत्रण की जरूरत है। वायु सेवा निगरानी को स्वचालित नेटवर्क आईएसीसीएस से अंजाम दिया जाते हैं। एस-400 और एमआर-300 प्रणालियों पर आधारित लागू हो जाने पर स्थिति साफ हो जाएगी। अंतर्दक्ष की निगरानी के लिए केंद्रीकृत निनंत्रण चाहिए।

### वैसी साइडलॉन्ग ने कहा है कि भारत एकीकृत थिएटर कमान में दूसरे देशों की आंख मूंदकर नकल नहीं करेगा और फैसला पूरी तरह देश की जरूरतों पर आधारित होगा। यह भी सच है कि सेना की अधिकांश कमान में नौसेना की कोई भूमिका नहीं है। ऐसे में हमें एकीकृत ट्राई-सर्विस ढांचा बनाने के बजाय इस बारे में सोचना चाहिए कि युद्ध शुरू होने पर तीनों सेनाओं की समन्वित मारक क्षमता किस तरह बढ़ाई जा सके।

### कानाफूसी

#### सीए का समर्थन

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विपक्ष द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के भारी विरोध को देखते हुए देशव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आदि की उपस्थिति में होगा। ये नेता सीएए के समर्थन में आयोजित रैलियों को संबोधित करेंगे। 21 जनवरी को गृहमंत्री अमित शाह लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। यह सभा उत्तर प्रदेश में इस चरण में बनी छह जन सभाओं में से पहली होगी। इस रैली में मध्य उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के सभी जिलों को शामिल किया जाएगा। राज्य पार्टी संगठन ने यह दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है कि ज्यादातर लोग इस नए कानून के समर्थन में हैं। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का कई राज्यों के लोग पिछले कई दिनों से विरोध कर रहे हैं।

#### आमने-सामने

पत्रकारों के प्रतिनिधि संगठन वित्त मंत्रालय की रिपोर्टिंग करने वाले अधिमान्य संवाददाताओं के नॉर्थ ब्लॉक में प्रवेश पर लगी रोक हटवाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाने जा रहे हैं। भारतीय प्रेस परिषद ने इस संबंध में भारतीय प्रेस क्लब और फॉरेन कॉर्रिस्पॉन्डेंट्स क्लब समेत विभिन्न पत्रकार संगठनों की शिकायत सुनने का निर्णय किया है। वित्त मंत्रालय ने रोक गत वर्ष जुलाई में लगाई थी। संवाददाताओं का कहना है कि इस आदेश के बाद अफसरशाह आधिकारिक रूप से उनसे मिलने में भी घबराने लगे हैं। उनका यह भी कहना है कि अन्य मंत्रालयों में अधिमान्य संवाददाताओं के लिए ऐसी कोई रोक नहीं है।



### आपका पक्ष

#### अर्थव्यवस्था की स्थिति और बजट

भारत की जीडीपी दर पांच साल के न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत की जीडीपी दर के पूर्वानुमान में कमी कर रही हैं। विशेषज्ञ मौजूदा स्थिति के लिए निवेश में कमी को कारण मान रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था निजी निवेश की कमी से जूझ रही है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई प्रयास किए हैं जैसे निवेश बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कॉर्पोरेट कर में कटौती, बैंकों का विलय, बैंकों को नई पूंजी देने, जीएसटी दर में कटौती और रीपो दर में कटौती का अभी तक कुछ खास असर नहीं दिखा है। प्रयासों की शृंखला में आगामी बजट में वित्त मंत्री को अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए निजी निवेश पर निर्भर रहने की अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा, क्योंकि अगर चुनौती है तो इसके लिए समाधान भी हैं। इसमें प्रमुख उपायों के रूप में कृषि और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के साथ



सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र के लिए विशिष्ट उपायों की घोषणा की जा सकती है। आर्थिक क्षेत्र को सुधारे के परिणामस्वरूप रोजगार की स्थिति और बिगड़ गई है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया आदि ने कुछ हद तक रोजगार सृजन का काम किया है। लेकिन आर्थिक सुस्ती ने इन योजनाओं के प्रभाव को सीमित कर दिया है, जबकि

#### देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए बजट में अलग प्रावधान करने चाहिए

स्वरूप में बदलाव से मनरेगा जैसी रोजगारमूलक योजना को संपत्ति सर्जक योजना बना दिया है। इसमें सुधार के लिए बजट में मनरेगा को लेकर कुछ घोषणा संभव है। इसके

अलावा कृषि और कृषि से जुड़े उद्योगों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशिष्ट उपायों की घोषणा भी की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र को वित्तपोषण को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोजगार आदि में निवेश करने से इस क्षेत्र को मंदी के प्रभाव से उभरने में काफी मदद मिलेगी। आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मांग, खपत और निवेश को बढ़ाया जाए। अन्य उपायों में बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च बढ़ाना, आयकर की दरों में कटौती, वित्तीय क्षेत्र को सुधारे एनबीएफसी में सुधार किया जाना आवश्यक है तथा अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों से निपटते हुए 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए अपेक्षित विकास दर को बनाए रखा जा सकता है।

सुजीत कुमार, बिलासपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं: संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं: lettershindi@bmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।